Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

01 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. कैबिनेट ने दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करने के लिए 99,446 करोड़ रुपये की ELI योजना को मंजूरी दी।

1 जुलाई, 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दी थी। यह 99,446 करोड़ रुपये की पहल है जिसका उद्देश्य पहली बार नौकरी पर रखने वाले लोगों और नियोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन के माध्यम से अगस्त 2025 और जुलाई 2027 के बीच 3.5 करोड़ से अधिक औपचारिक नौकरियां पैदा करना है।

• यह योजना EPF के माध्यम से पंजीकृत पहली बार ₹1 लाख/माह तक कमाने वाले कर्मचारियों को एक महीने की EPF वेतन सब्सिडी (₹15,000 तक) प्रदान करती है - जिसे दो भागों में वितरित किया जाता है। पात्रता को EPFO डेटाबेस के माध्यम से ट्रैक किया जाता है, और इसमें दूसरी किस्त जारी करने के लिए एक अनिवार्य वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल शामिल है।

• नियोक्ताओं को कम से कम छह महीने तक रखे गए प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए मासिक प्रोत्साहन (₹1,000-₹3,000) भी मिलता है। इस ढांचे के तहत, अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर रखने वाली विनिर्माण फर्में चार साल तक इन प्रोत्साहनों का दावा कर सकती हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों को दो साल के लिए कवर किया जाता है।

• इस योजना का लक्ष्य युवा पहली बार काम करने वालों को लक्षित करना है, जिसका लक्ष्य EPFO पंजीकरण के माध्यम से 1.92 करोड़ नए लोगों को औपचारिक रोजगार में लाना है। इससे उन नौकरियों को औपचारिक बनाने की उम्मीद है जो पहले सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर थीं।

Key Points:-

(i) एक विशेष विशेषता डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करती है: कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सब्सिडी आधार से जुड़े DBT और EPFO/पैन खातों के माध्यम से वितरित की जाएगी, जिससे लीकेज कम होगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

(ii) श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव (MoLE) ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी सब्सिडी पहली बार नौकरी करने वालों पर लागू होती है, जिनकी पहचान EPFO डेटा के माध्यम से की जाती है, जबकि नियोक्ताओं को भर्ती मानदंडों को पूरा करना होगा - सूक्ष्म फर्मों के लिए न्यूनतम दो, बड़ी इकाइयों के लिए पांच - वेतन और प्रतिधारण मानदंडों को डिजिटल रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।

(iii) ELI योजना केंद्रीय बजट 2024-25 के रोजगार पैकेज के अनुरूप है, जो MSDE और MoLE की पहलों का पूरक है। यह RDI और राष्ट्रीय खेल नीति के साथ-साथ कौशल और औपचारिकता के लिए एक व्यापक रणनीति का भी हिस्सा है - सभी को एक ही कैबिनेट सत्र में मंजूरी दी गई।

INTERNATIONAL

1. ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025: 758 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका शीर्ष पर और 64 के साथ भारत तीसरे स्थान पर।

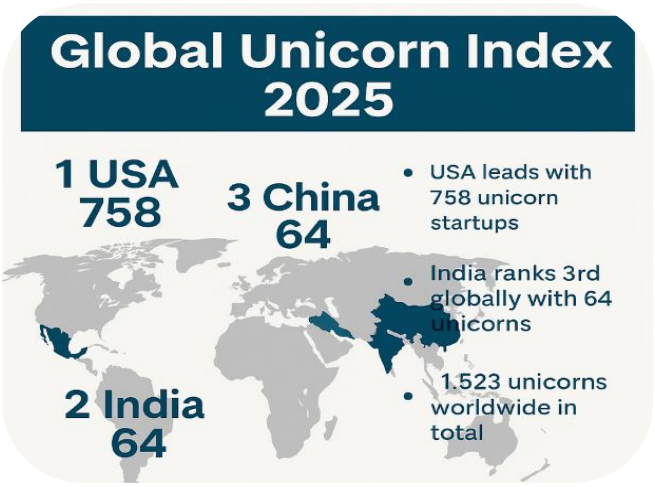

जून 2025 में, शंघाई स्थित हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 का अपना 7वां संस्करण जारी किया। संयुक्त राज्य अमेरिका 758 यूनिकॉर्न के साथ सूची में शीर्ष पर रहा, जबकि भारत ने 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जो वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है।

- **हुरुन की रिपोर्ट में दुनिया भर में कुल 1,523 यूनिकॉर्न दर्ज किए गए हैं - निजी स्वामित्व वाले स्टार्टअप जिनका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है - जो 52 देशों में संचालित हैं, जो 2024 की तुलना में 5% की वृद्धि को दर्शाता है। उनका संयुक्त मूल्यांकन 5.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो वैश्विक स्तर पर 22% अधिक है।**

- **संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना प्रभुत्व जारी रखा, दुनिया की 758 कंपनियों के साथ लगभग 49.8% यूनिकॉर्न का प्रतिनिधित्व किया - पिछले वर्ष की तुलना में 55 की शुद्ध वृद्धि। चीन 343 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे सबसे बड़े केंद्र के रूप में दूसरे स्थान पर है, जो 2024 तक 3 की वृद्धि है।**

Key Points:-

(i) भारत ने 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर अपना स्थान बनाए रखा, जो पिछले वर्ष के 67 से मामूली गिरावट है। यूनिकॉर्न की संख्या में अग्रणी भारतीय शहर बेंगलुरु (विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर), मुंबई (22वें स्थान पर) और गुरुग्राम (27वें स्थान पर) हैं - जो शहरी नवाचार केंद्रों को मजबूत करते हैं।

(ii) सेक्टर-वार, वैश्विक यूनिकॉर्न निर्माण में फिनटेक (197 यूनिकॉर्न), SaaS (151) और AI-संचालित कंपनियों (128) का नेतृत्व रहा। उल्लेखनीय रूप से, स्पेसएक्स (जिसका मूल्य 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर है) और ओपनएआई (300 बिलियन अमेरिकी डॉलर) दुनिया में शीर्ष दो सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न के रूप में उभरे।

(iii) चूंकि यूनिकॉर्न निर्माण में तेजी जारी है, हुरुन ने कहा कि जनवरी 2024-जनवरी 2025 के दौरान हर दो दिनों में लगभग एक नया यूनिकॉर्न उभरा। टाइगर ग्लोबल, सॉफ्टबैंक और सिकोइया कैपिटल जैसे निवेशक इस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे प्रभावशाली समर्थक बने हुए हैं।

2. चीन के क़िंगदाओ में 22वीं SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई और क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और द्विपक्षीय वार्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया।

25-26 जून, 2025 तक, 10-सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के रक्षा मंत्रियों की चीन के क़िंगदाओ में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून ने की। सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, सैन्य सहयोग का विस्तार करने और रणनीतिक संचार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि

उल्लेखनीय द्विपक्षीय वार्ता में सीमा तनाव और रक्षा आधुनिकीकरण पर चर्चा की गई।

• SCO के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून ने मजबूत संचार और साझा सुरक्षा के माध्यम से "शंघाई भावना" को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देकर सत्र की शुरुआत की। प्रतिभागियों ने समकालीन खतरों से निपटने के लिए संयुक्त अभ्यास, सूचना साझाकरण और सैन्य-चिकित्सा सहयोग जैसे व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की।

• भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2020 के गतिरोध के बाद चीन की अपनी पहली उच्च-स्तरीय यात्रा में भाग लेते हुए आतंकवाद के खिलाफ़ लड़ाई पर ज़ोर दिया। उन्होंने SCO सदस्यों से "बिना किसी पूर्वाग्रह के आतंकवाद की निंदा" करने का आग्रह किया, आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में इस्तेमाल करने वाले देशों को चेतावनी दी और सामूहिक विनाश के हथियारों और गैर-राज्य अभिनेताओं के खिलाफ़ कार्रवाई की वकालत की।

• राजनाथ सिंह ने आतंकवाद का जिक्र न होने के कारण संयुक्त घोषणापत्र का समर्थन करने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले को स्पष्ट रूप से स्वीकार करने की मांग की, तथा भारत के इस रुख पर जोर दिया कि आतंकवाद को नजरअंदाज करने के बजाय उसका समाधान किया जाना चाहिए।

Key Points:-

(i) द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष डोंग जून से मुलाकात की और भारत-चीन सीमा विवाद के लिए "स्थायी समाधान" पर चर्चा की। उन्होंने सैनिकों की वापसी, बेहतर संचार और अंततः सीमांकन पर संरचित वार्ता का प्रस्ताव रखा, जिससे गलवान के बाद तनाव कम होने का संकेत मिला और विश्वास बहाल हुआ।

(ii) एक अन्य महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम के तहत सिंह ने रूस के आंद्रे बेलौसोव से बातचीत की, जिसमें 2027 तक S-400 वायु रक्षा प्रणाली की समय पर आपूर्ति, सुखोई-30MKI लड़ाकू विमानों के उन्नयन और DRDO के प्रोजेक्ट कुशा पर प्रगति का आश्वासन प्राप्त हुआ, जिससे भारत की सामरिक क्षमताएं बढ़ेंगी।

(iii) बैठक में पाकिस्तान, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और भारत सहित सभी 10 SCO देशों ने भाग लिया। बैठक में बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच एक स्थिर क्षेत्रीय मंच के रूप में एससीओ की भूमिका को रेखांकित किया गया और रक्षा, आतंकवाद-रोधी और गैर-पारंपरिक सुरक्षा में सहयोग पर प्रकाश डाला गया।

3. तेगबीर सिंह 6 साल की उम्र में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए।

28 जून, 2025 को रूपनगर (पंजाब) के 6 वर्षीय तेगबीर सिंह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस (5,642 मीटर) पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। इस उपलब्धि को रूसी पर्वतारोहण अधिकारियों द्वारा आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया गया है।

• तेगबीर ने 20 जून, 2025 को चढ़ाई शुरू की और अत्यधिक ठंड (-20 डिग्री सेल्सियस), कम ऑक्सीजन और बर्फीले तूफानों के कारण दो असफल प्रयासों को पार करते हुए शिखर पर पहुँचे। उनकी अंतिम सफल चढ़ाई रूस के काकेशस पर्वतों में कठोर अल्पाइन परिस्थितियों में 9 दिनों में पूरी हुई।

• माउंट एल्ब्रस सात शिखरों का हिस्सा है और इसमें तेजी से ऊंचाई हासिल करना, शून्य से नीचे की रातें और अप्रत्याशित मौसम जैसी चुनौतियाँ हैं। उनकी यह उपलब्धि 2024 में भारत के ही वाघा कुशाग्र (7 वर्ष, 3 महीने) द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देती है।

Key Points:-

(i) तेगबीर को पर्वतारोही बिक्रमजीत सिंह घुमन ने प्रशिक्षित किया था, उनके पिता सुखिंदरदीप सिंह अभियान में शामिल हुए और उनकी माँ डॉ. मनप्रीत कौर, जो एक डॉक्टर हैं, ने महीनों पहले उनकी शारीरिक तैयारी और पोषण की देखरेख की।

(ii) यह उनका पहला उच्च-ऊंचाई वाला मील का पत्थर नहीं है - उन्होंने पहले एवरेस्ट बेस कैंप (अप्रैल 2024) तक ट्रेकिंग की और 5 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो (अगस्त 2024) पर चढ़ाई की, ऐसा करने वाले वे सबसे कम उम्र के एशियाई बन गए। ये चढ़ाई एल्ब्रस के लिए उनके प्रशिक्षण पथ का हिस्सा थीं।

(iii) उनकी चढ़ाई को काबर्डिनो-बाल्केरियन गणराज्य के पर्वतारोहण, रॉक क्लाइम्बिंग और खेल पर्यटन संघ द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिससे वे युवा धीरज, अनुशासन और साहसिक खेलों में भारत की बढ़ती प्रमुखता के वैश्विक प्रतीक बन गए।

BANKING & FINANCE

1. RBI डेटा पुष्टि करता है कि "वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विदेशी वित्तीय संपत्ति में 72% की वृद्धि होगी"।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया कि भारत की विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियां 1,033.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (मार्च 2024) से बढ़कर 1,139.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (मार्च 2025) हो गईं - 72% की वृद्धि - जो मजबूत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, उच्च मुद्रा और जमा होल्डिंग्स और आरक्षित परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित है, जो बढ़ती वैश्विक वित्तीय उपस्थिति को दर्शाती है।

• वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत की कुल बाह्य वित्तीय परिसंपत्तियों में 105.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जो भारत में विदेशी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों में वृद्धि से अधिक है, जो 74.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ी। परिणामस्वरूप, भारत पर गैर-निवासियों के शुद्ध दावों में 31.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई, जो बेहतर बाह्य वित्तीय स्वास्थ्य का संकेत है।

• विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में 54% से अधिक वृद्धि आरक्षित परिसंपत्तियों से हुई, जिसमें विदेशी मुद्रा और सोना शामिल है। शेष वृद्धि विदेशों में रखी गई मुद्रा और जमा शेष राशि और भारतीयों द्वारा विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश के कारण हुई।

• मार्च 2025 तक भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का अनुपात 74.1% से बढ़कर 77.5% हो गया। यह व्यापक सुरक्षा बढ़ी हुई बाहरी वित्तीय लचीलापन और अधिक संतुलित अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति को रेखांकित करती है।

Key Points:-

(i) अकेले जनवरी-मार्च 2025 तिमाही में, भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जबकि भारत में विदेशी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों में केवल 25.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई - जो आउटबाउंड पूंजी प्राथमिकताओं पर जोर देती है।

(ii) भारत पर गैर-निवासियों के शुद्ध दावे दिसंबर 2024 में 364.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में मार्च 2025 तक घटकर 330 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गए, जिसका मुख्य कारण अत्यधिक परिसंपत्ति वृद्धि है - जो विदेशी शुद्ध जोखिम को कम करने में एक सकारात्मक संकेत है।

(iii) RBI के आंकड़े भारतीय संस्थाओं - निजी और सार्वजनिक दोनों - द्वारा उच्च वैश्विक निवेश और मुद्रा विविधीकरण की दिशा में रणनीतिक बदलाव को दर्शाते हैं, जो व्यापक वित्तीय स्थिरता लक्ष्यों और मजबूत वैश्विक स्थिति के साथ संरेखित है।

ECONOMY & BUSINESS

1. HDFC म्यूचुअल फंड ने ओपन मार्केट डील के जरिए सुंदरम फास्टनर्स में 0.65% हिस्सेदारी ₹137 करोड़ में हासिल की।

HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) की सहायक कंपनी HDFC म्यूचुअल फंड ने हाल ही में जून 2025 में सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड के 13.70 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जो 0.65% हिस्सेदारी के बराबर है। ₹137.02 करोड़ का निवेश ₹1,000 के औसत शेयर मूल्य पर खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से किया गया, जिससे कंपनी में HDFC MF की कुल हिस्सेदारी 4.27% से बढ़कर 5.02% हो गई।

• सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है, TVS समूह के तहत एक प्रमुख ऑटोमोटिव घटक आपूर्तिकर्ता है। 1966 में स्थापित, कंपनी घरेलू और वैश्विक ऑटोमोटिव मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) दोनों के लिए एक अग्रणी निर्माता बन गई है, जिसमें नवाचार, इंजीनियरिंग और विविध उत्पाद लाइनों के लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा है।

• कंपनी का उत्पाद पोर्टफोलियो फास्टनर्स, पावरट्रेन घटक, सिन्नटर मेटल उत्पाद, रेडिएटर कैप्स, कोल्ड एक्सट्रूडेड पार्ट्स, वॉटर पंप, ऑयल पंप और विंड एनर्जी कंपोनेंट्स तक फैला हुआ है। इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत मौजूदगी है, जिसमें भारत, चीन और यूरोप में उत्पादन इकाइयाँ शामिल हैं, और यह उत्तर अमेरिका तथा यूरोपीय बाजारों में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है।

Key Points:-

(i) HDFC MF का रणनीतिक निवेश भारत के ऑटो सहायक क्षेत्र में व्यापक सुधार के बीच हुआ है, जो बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पादन और विविधतापूर्ण, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं की ओर वैश्विक बदलाव से प्रेरित है। सुंदरम फास्टनर्स की मजबूत बैलेंस शीट, निर्यात क्षमता और R&D में निवेश इसे क्षेत्रीय अनुकूल परिस्थितियों से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में रखते हैं।

(ii) संबंधित बाजार घटना में, सिंगापुर स्थित क्यूब मोबिलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने क्यूब हाईवेज ट्रस्ट- जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित एक बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (InvIT) है- में 0.59% हिस्सेदारी (लगभग 79.25 लाख यूनिट) ₹127.50 प्रति यूनिट की दर से ₹101 करोड़ में बेच दी।

(iii) क्यूब हाईवे ट्रस्ट, जो टोल सड़कों और राजमार्ग परिसंपत्तियों में निवेश करता है, InvITs के माध्यम से स्थिर रिटर्न चाहने वाले दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. केंद्र ने CBDT अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल का कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ाया।

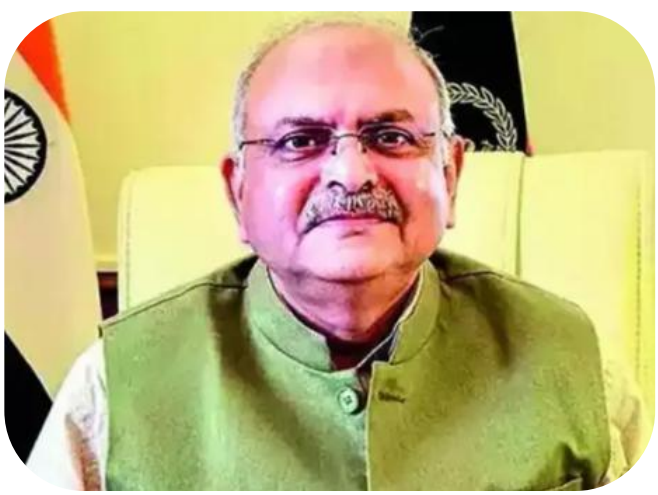

28 जून, 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी। उनका नया कार्यकाल 1 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तक चलेगा, जो भारत के प्रत्यक्ष कर नेतृत्व में निरंतरता को मजबूत करेगा।

• 1988 बैच के IRS अधिकारी रवि अग्रवाल ने मूल रूप से जून 2024 में CBDT अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था और उन्हें जून 2025 तक अनुबंध के आधार पर बनाए रखा गया था। नवीनतम विस्तार, 1 जुलाई 2025 से प्रभावी, प्रत्यक्ष कर प्रशासन में चल रहे सुधारों के बीच अनुभवी नेतृत्व को बनाए रखता है।

• विस्तार का एक प्रमुख कारण जटिल कर विवादों को सुलझाने में निरंतरता और कर न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में आयकर अधिकारियों से पारदर्शिता, करदाता-अनुकूल प्रक्रियाओं और 577,000 से अधिक लंबित कर अपीलों के शीघ्र निपटान को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

• उनके नेतृत्व में, CBDT आयकर विभाग के लिए नीति और प्रशासनिक नियोजन की देखरेख करता है, जिसमें वरिष्ठ नियुक्तियाँ, विभागीय स्थानांतरण और ओईसीडी और UN जैसे वैश्विक कर मंचों में प्रतिनिधित्व शामिल है। अग्रवाल की गहन विशेषज्ञता ने उन्हें वित्त मंत्रालय के एक विश्वसनीय सलाहकार के रूप में स्थापित किया है।

Key Points:-

(i) रवि अग्रवाल की पुनर्नियुक्ति में अनुबंध के आधार पर अनुभवी IRS अधिकारियों को नियुक्त करने की प्रथा जारी है, जिसमें नियमों में ढील दी गई है, जिससे पुनर्नियुक्त केंद्रीय सरकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति की आयु से आगे भी सेवा करने की अनुमति मिलती है। ये शर्तें कर तंत्र में विनियामक लचीलापन और संस्थागत स्मृति सुनिश्चित करती हैं।

(ii) अग्रवाल के नेतृत्व में CBDT आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्तों को प्रभावी पर्यवेक्षण करने, आकलन

में प्रासंगिक पूछताछ सुनिश्चित करने और तुच्छ जांच नोटिसों को खत्म करने का निर्देश दे रहा है। यह कर प्रणाली में सरलता और पारदर्शिता के व्यापक प्रयास के अनुरूप है।

(iii) अग्रवाल का अनुबंध विस्तार आयकर विभाग में 35 वर्षों से अधिक के उनके विशिष्ट करियर का समापन है और यह सर्वोच्च कर नीति निकाय के भीतर स्थिरता पर सरकार के फोकस को पुष्ट करता है। उनके निरंतर नेतृत्व को वित्त वर्ष 2025-26 में कर अनुपालन और विवाद समाधान प्रयासों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

2. ACC ने पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) का नया प्रमुख नियुक्त किया, कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से शुरू होगा।

28 जून, 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 1989 बैच के IPS अधिकारी (पंजाब कैडर) पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) का नया सचिव नियुक्त करने को मंजूरी दे दी। वे 1 जुलाई से रवि सिन्हा की जगह दो साल का कार्यकाल शुरू करेंगे।

• पराग जैन वर्तमान में एविएशन रिसर्च सेंटर (ARC) का नेतृत्व करते हैं - R&AW की तकनीकी शाखा जो हवाई निगरानी और इमेजरी इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार है। उनकी पदोन्नति तकनीकी और मानवीय खुफिया दोनों क्षेत्रों में उनके दो दशक के अनुभव को दर्शाती है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े ऑपरेशनों को विशेष रूप से संभालना शामिल है।

• उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में अपनी रणनीतिक भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके दौरान ARC ने पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों पर सटीक हमलों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। इस ऑपरेशन ने तकनीकी खुफिया जानकारी और परिचालन योजना में उनकी गहरी विशेषज्ञता को प्रदर्शित किया।

Key Points:-

(i) पराग जैन की पृष्ठभूमि में पंजाब में आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण कार्य, पाकिस्तान डेस्क पर कार्यकाल और जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के दौरान खुफिया जानकारी का नेतृत्व करना शामिल है। उन्होंने श्रीलंका और कनाडा में भारतीय मिशनों में भी काम किया है, जहाँ उन्होंने सूचना-संग्रह और आतंकवाद-रोधी अभियान पर काम किया है।

(ii) सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (2005) प्राप्त करने वाले जैन अपनी विवेकपूर्ण नेतृत्व शैली और परिचालन कठोरता के लिए जाने जाते हैं। जुलाई 12025 से प्रभावी उनकी नियुक्ति, बाहरी खुफिया जानकारी पर निरंतरता और बढ़े हुए ध्यान की पुष्टि करती है, जो उभरती भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत की रणनीतिक प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

3. केशवन रामचंद्रन को RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया।

1 जुलाई, 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केशवन रामचंद्रन को प्रूडेंशियल रेगुलेशन डिवीज़न का कार्यभार संभालते हुए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। इससे पहले वे जोखिम निगरानी विभाग में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, उनके पास मुद्रा और बैंकिंग पर्यवेक्षण में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है।

• तीन दशक से ज़्यादा के करियर में रामचंद्रन ने मुद्रा प्रबंधन, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण, वित्तीय प्रशिक्षण और प्रशासन में अहम भूमिकाएँ निभाई हैं। इस पदोन्नति से पहले, उन्होंने RBI के जोखिम निगरानी विभाग का नेतृत्व किया था, जो बैंकिंग स्थिरता सुनिश्चित करने में उनके गहन अनुभव को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) रामचंद्रन ने रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में काम किया है, जहाँ उन्होंने व्यावसायिक विकास की देखरेख की। वे पाँच साल से अधिक समय तक केनरा बैंक बोर्ड में RBI के नामित सदस्य भी रहे और दो साल तक ICAI के ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड में योगदान दिया, जिससे उनके विनियामक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला।

(ii) शैक्षिक रूप से, रामचंद्रन के पास बैंकिंग और वित्त में एमबीए की डिग्री है, साथ ही ACCA, UK द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी है। वह भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (IIBF) के प्रमाणित एसोसिएट हैं - ऐसे प्रमाण-पत्र जो उनकी व्यापक विनियामक जिम्मेदारियों का समर्थन करते हैं।

(iii) कार्यकारी निदेशक के रूप में, वे विनियमन विभाग का नेतृत्व करेंगे, बैंकों और एनबीएफसी के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को औपचारिक बनाने, वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनकी पदोन्नति RBI के जोखिम शासन और विनियामक निरीक्षण पर जोर देने के साथ संरेखित है ताकि एक लचीला वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित किया जा सके।

SPORTS

1. लैंडो नोरिस ने 2025 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता, इस सीज़न की अपनी तीसरी F1 जीत हासिल की।

जून 2025 में, मैकलारेन के ब्रिटिश फॉर्मूला 1 (F1) ड्राइवर लैंडो नोरिस ने स्पीलबर्ग, स्टायरिया में रेड बुल रिंग में आयोजित ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स में पहला स्थान हासिल करके 2025 F1 सीज़न की अपनी तीसरी जीत हासिल की। इस रेस को आधिकारिक तौर पर 2025 ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स (GP) का नाम दिया गया और इसे F1 MSC क्रूज़ ऑस्ट्रियाई GP कैलेंडर में शामिल किया गया।

• नॉरिस की हालिया जीत उनके करियर की कुल 7वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत है और 2025 ड्राइवर्स चैंपियनशिप में उनकी स्थिति को काफी हद तक बढ़ा देती है। अब वह 201 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, टीम के साथी ऑस्कर पियास्ट्री से पीछे हैं, जो 216 अंकों के साथ सबसे आगे हैं। पोडियम पर फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने जगह बनाई, जो तीसरे स्थान पर रहे।

• रेस के दौरान नॉरिस ने अपनी अग्रणी स्थिति को कुशलतापूर्वक बनाए रखा। उन्होंने फेरारी के चार्ल्स लेक्लर को पीछे छोड़ा और लगातार अंतर बनाए रखने में सफल रहे, अंततः पियास्ट्री से 2.695 सेकंड आगे रहे। यह जीत 2025 सीज़न में मैकलारेन के निरंतर प्रभुत्व को दर्शाती है।

• चार्ल्स लेक्लर, जिन्होंने पोल पोजीशन से रेस शुरू की थी, बढ़त को जीत में नहीं बदल सके और तीसरे स्थान पर रहे। इस बीच, मर्सिडीज के ड्राइवर लुईस हैमिल्टन और जॉर्ज रसेल क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर रहे, जिन्होंने अपने क्वालीफाइंग पोजीशन से मामूली सुधार दिखाया।

Key Points:-

(i) शुरुआती लैप में एक बड़ी घटना घटी जब रेड बुल के 4 बार के विश्व चैंपियन मैक्स वेरस्टैपेन को मर्सिडीज के किमी एंटोनेली से हुई दुर्घटना के कारण रिटायर होना पड़ा। वेरस्टैपेन के जल्दी बाहर होने से खिताब की दौड़ में उनकी स्थिति प्रभावित हुई, जहां अब वे मैकलारेन के दोनों ड्राइवरों से काफी पीछे हैं।

(ii) इस जीत से 25 अंक प्राप्त करने के बाद, नॉरिस अब शीर्ष स्थान के लिए टीम के साथी पियास्ट्री के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में हैं। ऑस्ट्रियाई GP के बाद की स्थिति में पियास्ट्री के 216 अंक, नॉरिस के 201 अंक और वेरस्टैपेन के 155 अंक पीछे हैं। मैकलारेन की यह आंतरिक लड़ाई ब्रिटिश GP जैसी आगामी दौड़ों में और भी तेज होने वाली है।

(iii) ऑस्ट्रियाई GP, 1964 में अपनी पहली आधिकारिक विश्व चैम्पियनशिप रेस के बाद से एफ1 इतिहास का हिस्सा है, यह 4.326 किलोमीटर के सर्किट के 71 लैप्स पर आयोजित की गई थी, जिसकी कुल रेस दूरी 307.236 किलोमीटर थी। यह आयोजन फ़ेडरेशन इंटरनेशनेल डे ल'ऑटोमोबाइल (FIA) के तहत आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।

2. ICC ने जुलाई 2025 से प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए नई खेल स्थितियों को मंजूरी दी।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने हाल ही में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में खेल की स्थितियों में व्यापक बदलाव पेश किए हैं, जो जून-जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। इन परिवर्तनों का उद्देश्य खेल की गति में सुधार करना, खिलाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाना और नई तकनीक और प्रक्रियात्मक अपडेट के माध्यम से निर्णय लेने में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

• टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव करते हुए, ICC ने 17 जून, 2025 से ओवरों के बीच 60 सेकंड का स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया है। अगर कोई फील्डिंग टीम एक पारी में दो बार से ज़्यादा इस सीमा को पार करती है, तो उस पर पाँच रन की पेनल्टी लगाई जाएगी। यह नियम तेज़ ओवर रेट को बढ़ावा देता है और मैच की गति को बनाए रखता है।

• 2 जुलाई 2025 से वनडे मैचों में अंतिम 16 ओवरों के लिए केवल एक गेंद का उपयोग किया जाएगा। 34वें ओवर के बाद, कप्तान को खेल जारी रखने के लिए इस्तेमाल की गई दो गेंदों में से एक को चुनना होगा। इस बदलाव का उद्देश्य रिवर्स स्विंग को बहाल करना और डेथ ओवरों के दौरान बल्ले-गेंद के बीच प्रतिस्पर्धा को संतुलित करना है।

• ICC ने बाउंड्री कैच से जुड़े नियम को स्पष्ट किया है। अब फील्डर बाउंड्री से बाहर हवा में रहते हुए गेंद से सिर्फ़ एक बार ही संपर्क कर सकते हैं और कैच पूरा करने के लिए उन्हें पूरी तरह रस्सी के अंदर उतरना होगा। इससे ग्रे एरिया खत्म हो जाता है और सभी मैचों और फॉर्मेट में एक समान व्याख्या सुनिश्चित होती है।

Key Points:-

(i) निर्णय समीक्षा प्रणाली (DRS) में नए प्रावधान जोड़े गए हैं। यदि बल्लेबाज को एक मोड में आउट करार दिया जाता है, जैसे कि कैच, तो फील्डिंग टीमें अभी भी दूसरे मोड के लिए समीक्षा कर सकती हैं, जैसे कि LBW। साथ ही, कई तरह के आउट होने के मामलों में, अब निर्णयों का मूल्यांकन तार्किक, कालानुक्रमिक क्रम में किया जाएगा।

(ii) खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए एक सख्त कदम उठाते हुए, टीमों को अब मैच से पहले पाँच कन्कशन सब्सटीट्यूट की घोषणा करनी होगी। अगर किसी खिलाड़ी को मैच के दौरान कन्कशन का पता चलता है, तो उसे कम से कम सात दिनों के लिए बाहर कर दिया जाएगा। घरेलू लीग भी पूर्णकालिक समान-से-समान चोट प्रतिस्थापन का परीक्षण करेंगी।

(iii) ICC ने बॉल पॉलिशिंग के लिए लार पर प्रतिबंध जारी रखा है, लेकिन स्वचालित बॉल रिप्लेसमेंट की आवश्यकता में ढील दी है। अंपायर अब यह आकलन करेंगे कि बॉल की स्थिति में कोई बदलाव हुआ है या नहीं। लार का जानबूझकर इस्तेमाल करने पर पांच रन की पेनल्टी लगेगी, जिससे खेल में अनावश्यक व्यवधान के बिना स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा।

IMPORTANT DAYS

1. GST दिवस 2025, 1 जुलाई को मनाया गया, जो भारत के एकीकृत अप्रत्यक्ष कर सुधार के 8 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

भारत ने 1 जुलाई, 2025 को GST दिवस मनाया, जो 2017 में माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के आठ साल पूरे होने का प्रतीक है। यह दिन भारत के एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में बदलाव की याद दिलाता है, जिसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना और औपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

• 2025 में GST दिवस की आधिकारिक थीम "GST–करों को सरल बनाना; नागरिकों को सशक्त बनाना" थी। इस थीम की घोषणा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने की थी, और इसने करदाताओं के बोझ को कम करने और आर्थिक पारदर्शिता बढ़ाने में GST की भूमिका पर जोर दिया। तिरुवनंतपुरम CGST जोन को करदाता सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय मान्यता मिली।

• GST दिवस से पहले, CBIC ने जागरूकता अभियान के रूप में 17 से 30 जून, 2025 तक GST पखवाड़ा मनाया। इसमें करदाता सुविधा डेस्क, GST रिटर्न दाखिल करने में सहायता केंद्र और फिट इंडिया बैनर के तहत सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे

आउटरीच कार्यक्रम शामिल थे। इस पहल का उद्देश्य हितधारकों को नए अनुपालन मानदंडों और GST प्रणाली के लाभों के बारे में शिक्षित करना था।

Key Points:-

(i) जुलाई 2025 से प्रभावी, प्रमुख अनुपालन सुधार पेश किए गए। GSTR-3B रिटर्न को GSTR-1 से स्वचालित रूप से भरा गया और जमा करने के बाद संपादन योग्य नहीं बनाया गया, जबकि सुधार के लिए अब संशोधित GSTR-1A की आवश्यकता होगी। जवाबदेही में सुधार और सिस्टम के दुरुपयोग को कम करने के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए एक नई तीन साल की सीमा अवधि भी लागू की गई।

(ii) मई 2025 में GST संग्रह ₹2.01 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के आंकड़ों से 16.4% अधिक है। यह वृद्धि बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि, बेहतर अनुपालन और कर आधार के विस्तार को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में, कुल GST राजस्व ₹18.3 लाख करोड़ को पार कर गया, जिससे यह GST के लागू होने के बाद से सबसे मजबूत वित्तीय वर्ष बन गया।

(iii) GST दिवस 2025 ने भारतीय बाजार को एकीकृत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और GST परिषद के माध्यम से संघीय कर सहयोग को मजबूत करने में योजना के दीर्घकालिक लाभों पर प्रकाश डाला। इसने भारत के कर ढांचे को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अपनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ भी जोड़ा, जिससे GST स्वतंत्र भारत में सबसे सफल कर सुधारों में से एक बन गया।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. DRDO ने उन्नत स्टेल्थ डिटेक्शन के लिए भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार पेश किया।

जून 2025 के अंत में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने भारत के पहले फोटोनिक रडार के विकास की घोषणा की, जो रडार प्रौद्योगिकी में एक बड़ी छलांग है। यह प्रणाली, जो वर्तमान में प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर 6 पर है, आगामी परीक्षणों से पहले अल्ट्रा-हाई रिज़ॉल्यूशन और एंटी-स्टील्थ क्षमताओं के लिए फोटोनिक घटकों को एकीकृत करती है।

- **भारत का फोटोनिक रडार पारंपरिक रेडियो तरंगों के बजाय लेजर-मॉड्यूलेटेड ऑप्टिकल सिग्नल का उपयोग करता है, ताकि बेहतर स्पष्टता, सब-मिलीमीटर रिज़ॉल्यूशन और कम इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप के साथ वस्तुओं का पता लगाया जा सके। यह 100GHz-THz स्पेक्ट्रम में संचालित होता है, जिससे लक्ष्य की स्पष्ट इमेजिंग और बेहतर स्टेल्थ डिटेक्शन मिलता है।**

- **यह सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी घटकों, जैसे कि हाई-स्पीड ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर और फाइबर-आधारित सिग्नल प्रोसेसर से बनाया गया है, जो महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। रडार कम पता लगाने की क्षमता भी प्रदान करता है, जिससे विरोधियों के लिए पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का उपयोग करके अवरोधन करना मुश्किल हो जाता है।**

Key Points:-

(i) DRDO का लक्ष्य स्थिर प्लेटफॉर्म पर रडार को

एकीकृत करना है, इसके बाद समुद्री और हवाई निगरानी के लिए यूएवी और नौसेना के जहाजों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जल्द ही इसके परिचालन परीक्षण की उम्मीद है, जिससे भारत अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ और जापान जैसे देशों के एक छोटे समूह में शामिल हो जाएगा जो फोटोनिक रडार सिस्टम का परीक्षण कर रहे हैं।

(ii) यह तकनीक कई तरह के अनुप्रयोग प्रस्तुत करती है: स्टील्थ विमान का पता लगाना, हाइपरसोनिक मिसाइलों पर नज़र रखना, अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करना, और यातायात नियंत्रण या आपदा निगरानी में सुरक्षित नागरिक उपयोग। आगामी परीक्षणों के साथ, यह स्वदेशी रडार भारत के रक्षा टूलकिट में एक रणनीतिक परिसंपत्ति बनने के लिए तैयार है।

BOOKS & AUTHORS

1. जगदीश शुक्ला ने जलवायु और अराजकता सिद्धांत पर संस्मरण "ए बिलियन बटरफ्लाईज़" का विमोचन किया।

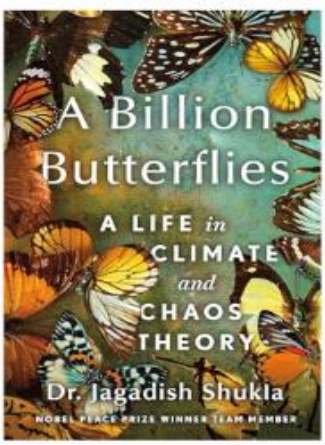

प्रसिद्ध भारतीय मौसम विज्ञानी जगदीश शुक्ला ने हाल ही में पैन मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित "ए बिलियन बटरफ्लाईज़: ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड कैओस थ्योरी" शीर्षक से एक संस्मरण लिखा है। यह पुस्तक जलवायु गतिशीलता, पूर्वानुमान और मौसम विज्ञान के विकास को समझने में उनकी व्यक्तिगत और वैज्ञानिक यात्रा का वर्णन करती है।

• पुस्तक में, शुक्ला ने एक ग्रामीण भारतीय गांव से एक अग्रणी वैश्विक जलवायु वैज्ञानिक बनने तक के अपने उत्थान को साझा किया है। उन्होंने "बिलियन बटरफ्लाई" प्रयोगों की अवधारणा पेश की, जिसने मौसम की अप्रत्याशितता के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती दी, जलवायु पूर्वानुमान में अराजकता सिद्धांत की भूमिका पर जोर दिया।

Key Points:-

(i) संस्मरण जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका पर प्रकाश डालता है, जिसे अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर के साथ संयुक्त रूप से 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उसी वर्ष, उन्हें मौसम विज्ञान में सर्वोच्च वैश्विक सम्मान, प्रतिष्ठित IMO पुरस्कार मिला।

(ii) विज्ञान और इंजीनियरिंग में उनके योगदान के लिए जगदीश शुक्ला को 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। वह वर्तमान में अमेरिका के वर्जीनिया स्थित जॉर्ज मेसन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं तथा वैश्विक जलवायु नीति और अनुसंधान में एक प्रभावशाली आवाज बने हुए हैं।

Static GK

Federation Internationale de l'Automobile (FIA)	राष्ट्रपति : मोहम्मद बेन सुलेयम	मुख्यालय : पेरिस, फ्रांस
ICC	स्थापना: 1909	मुख्यालय: दुबई
SCO	मुख्यालय: बीजिंग, चीन	स्थापना: 15 जून 2001
RBI	संस्थापक: ब्रिटिश राज	स्थापना: 1 अप्रैल 1935
Research & Analysis Wing (R&AW)	संस्थापक: आर.एन. काओ, इंदिरा गांधी	मुख्यालय: नई दिल्ली
DRDO	अध्यक्ष: समीर वी. कामत	मुख्यालय: नई दिल्ली